

लविवि : केंद्रीकृत प्रवेश काउंसलिंग के लिए कॉलेजों को देना होगा शुल्क

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन पहली बार सत्र 2020-21 में कॉलेजों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कॉलेजों को भारी-भरकम शुल्क भी देना होगा। रजिस्ट्रार डॉ. विनोद सिंह ने सहयुक्त कॉलेजों को पत्र भेजकर कहा है कि विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 से केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत विवि के साथ सहयुक्त महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश करेगा। इसमें कॉलेज प्रवेश सहभागिता शुल्क जमा करके विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से ले सकते हैं। इसके लिए प्रोफेशनल फॉर्म में प्रति महाविद्यालय प्रति विषय 01 लाख और 18% सर्विस टैक्स, सामान्य पाठ्यक्रम में प्रति कोर्स 50 हजार और 18% सर्विस टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा है कि कॉलेज निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन कर 05 जुलाई तक अवगत कराएंगे, जिसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इसलिए शुरू की योजना

लखनऊ विवि में प्रवेश के लिए काफी संख्या में विद्यार्थी आवेदन करते हैं, जो सीटों के साथे लगभग लगने होते हैं। ऐसे में विवि ने कॉलेजों के लिए भी केंद्रीकृत प्रवेश की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया ताकि विवि के साथ-साथ विद्यार्थी चाहे तो कॉलेज को भी वरीयता दे सकते हैं।



NBT Page 4

50 जिलों में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा

पहले 73 जिलों में होनी थी, कम परीक्षा केंद्र वाले जिले सूची से हटाए गए

■ **एनबीटी, लखनऊ :** बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार प्रदेश के 50 जिलों में होगी। पहले यह 73 जिलों में होनी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम परीक्षा केंद्र वाले जिलों को लिस्ट से हटा दिया है। हालांकि, एलयू के कुलसचिव विनोद कुमार सिंह का कहना है कि एलयू प्रशासन सम्भवतः पांच जुलाई तक अंतिम केंद्रों की सूची जारी कर सकता है। वहीं 10 से 15 जुलाई के बीच एडमिट कार्ड भी जारी हो सकते हैं। सभी केंद्रों की समीक्षा करने के बाद जिलों को कम करने का निर्णय लिया गया है। सप्ताह भर पहले अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी विकल्प में जो जिले चुने थे, उनमें दो या तीन से ज्यादा केंद्र नहीं बन पा रहे थे। इसकी वजह से उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है।

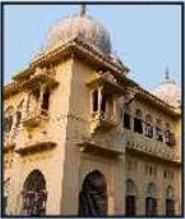
एक एडमिशन फॉर्म के लिए कॉलेजों को 5 जुलाई तक देना होगा ब्योरा

■ **एनबीटी, लखनऊ:** लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों को भी दखिलों की केन्द्रीयकृत व्यवस्था से जुड़ने के लिए यूजी, पीजी कोर्सेस और सीटों की संख्या समेत कोई जानकारी देनी होगी। इसके लिए एलयू ने अपनी वेबसाइट पर प्रोफार्मा भी तैयार कर लिया है, जिसे कॉलेजों को आरटीजीएस शुल्क के साथ भरकर पांच जुलाई तक ईमेल करना होगा। दरअसल, डीयू की तर्ज पर एलयू और सम्बद्ध कॉलेजों में अब प्रवेश के लिए छात्रों को सिर्फ एक एडमिशन फॉर्म

भरना होगा। बुधवार को एलयू प्रशासन की मीटिंग में हुए निर्णय में सभी संबद्ध महाविद्यालय को जुड़ने के लिए तीन दिन का समय भी दिया गया है।

ये जानकारी देनी होगी

यूजी जनरल, यूजी प्रोफेशनल, पीजी जनरल और पीजी प्रोफेशनल कोर्सेस की सूची, कॉलेज नाम, यूजीआरसी कोड, पता, पिन कोड, प्राचार्य का नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आइडी, कोर्स का नाम, विषय, श्रेणी, सीट की संख्या, प्रवेश सहभागिता शुल्क और कुल जमा शुल्क का ब्योरा देना होगा।



RASHTRIYA SAHARA Page 5

लविवि में लागू होगी केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रणाली

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने लविवि से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर सत्र 2020-21 से केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस केन्द्रीकृत प्रवेश प्रणाली के तहत इच्छुक संबद्ध महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही सम्पादित करा सकते हैं। रजिस्ट्रार द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को पांच जुलाई 2020 तक ईमेल में भेजे आवेदन पत्र के द्वारा केन्द्रीकृत प्रवेश प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए सूचना प्रेषित करने के लिए कहा गया है।

संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 29 को

लखनऊ (एसएनबी)। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर झंझार अब खस हो गया है। शासन ने 29 जुलाई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा करने के लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मान लिया है। प्रवेश परीक्षा के परिणाम 28 अगस्त को परीक्षा परिणाम जारी होंगे और 14 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कई जाने वाली राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा-2020 के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय को 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए पहली बार निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय लिया है। शासन ने परीक्षा केंद्रों पर नकल न हो, इसके लिए कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र बनाने में शासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों को ही प्राथमिकता देने के लिए कहा है। किसी भी दशा में निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जरूरी है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित चहारदीवारी हो और सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हों। प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे में वायस रिकार्डर और डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।

सभी जिलों में बनेगी परीक्षा संचालन कमेटी : शासन ने प्रत्येक जिले में परीक्षा संचालन कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कमेटी में डीएम द्वारा नामित अधिकारी के अलावा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और लखनऊ विश्वविद्यालय के एक नामित अधिकारी होंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी।

सात जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची 4.31 लाख विद्यार्थियों ने किया है आवेदन, रिजल्ट 28 को

यूजी-पीजी के सामान्य व प्रोफेशनल पाठ्यक्रम

■ **यूजी सामान्य पाठ्यक्रम :** बीए, बीए ओनर्स, बीकॉम, बीएससी बायो युप, बीएससी मैथ युप

■ **यूजी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम :** बीकॉम ओनर्स, बीवोक रनिवेबल एनर्जी, बीसीए, बीबीए/बीएफए, बीजेएससी, एलएलबी फाइव ईयर, बीबीए, बीएलएड

पीजी सामान्य पाठ्यक्रम

एमए एंथ्रोपोलॉजी, एमए एआईएच एंड आर्कियोलॉजी, एमए अरब कल्चर, एमए अरोबिक, एमए बायो स्टेटिस्टिक्स, एमए डिफेंस स्टडीज, एमए इकोनॉमिक्स, एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश, एमए फ्रेंच, एमए जियोग्राफी, एमए हिंदी, एमए होम साइंस, एमए ज्योतिर्विज्ञान, एमए लिंग्विस्टिक, एमए मैथमेटिक्स, एमए मॉडर्न ओरेबिक, एमए पर्सियन, एमए फिलॉसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी, एमए संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी, एमए स्टेटिस्टिक्स, एमए उर्दू, एमए वुमेन स्टडीज, एमए एमआईएच/केपोसिट हिस्ट्री/वेस्टर्न हिस्ट्री, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर सोशल वर्क, एमकॉम एलएइड इकोनॉमिक्स, एमकॉम कोमर्स, एमएससी बायो केमिस्ट्री, एमएससी बांटनी/प्लांट, साइंस/माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी स्टेटिस्टिक्स

पीजी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम

एलएलएम, एमएड, एमपीएड, एमएससी कम्प्यूटर साइंस, एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमएससी रिनवेबल एनर्जी, एमएससी एलएइड जियोलॉजी, एमएससी बायो स्टेटिस्टिक्स, एमएससी फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बायो टेक्नोलॉजी, एमएससी मास कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमबीए, मास्टर इन पॉपुलेशन स्टडीज, मास्टर इन बिजिनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन होस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन, एमए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, एमए फॉरेंसिक साइंस, एमए इयूमन कॉन्सिस्नेन्स एंड यौगिक साइंस, एमए जर्नलिज्म एंड मास कॉम, एमएससी फॉरेंसिक साइंस व बीपीएड

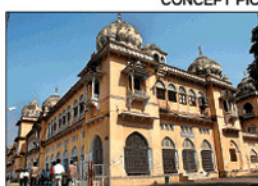
बीलिव, एमलिव, एलएलबी,

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता शासन ने 29 जुलाई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को हरी झंडी दे दी है। 28 अगस्त को परीक्षा परिणाम घोषित होंगे और 14 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। शासनादेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्रों में और यथासंभव जिला मुख्यालय के निकट ही बनाए जाएं। शासन ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित चहारदीवारी और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में वायस रिकार्डर व डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस कोना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक व कनिष्ठ द्वारा नामित एक अधिकारी होगा।

i-NEXT Page 4

बीएड एंट्रेंस एग्जाम अब 73 नहीं सिर्फ 50 जिलों में होंगे

पहले प्रदेश के 73 जिलों में होनी थी यह परीक्षा कम आवेदन वाले जिलों से हटाए गए परीक्षा केंद्र



10 से 15 जुलाई तक जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता शासन ने 29 जुलाई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा करने के लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मान लिया है। प्रवेश परीक्षा में कुल 4.31 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 28 अगस्त को परीक्षा परिणाम जारी होंगे और 14 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। शासन ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित चहारदीवारी और सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हों। प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे में वायस रिकार्डर और डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।

AMRIT VICHAR Page 2

हरी झंडी

29 को होगी परीक्षा, सभी केन्द्रों की सूची लखनऊ विश्वविद्यालय से 7 तक शासन में तलब

बीएड प्रवेश परीक्षा कराने को शासन की मंजूरी

अमृत विचार लखनऊ

तमाम ऊहापोह की स्थिति के बाद आखिरकार शासन ने यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली जिम्मेदारियों की व्यवस्था और तैयारियों का ब्योरा शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 7 जुलाई तक तलब किया है। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से सरकार को बताना होगा कि परीक्षाार्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों की संख्या कितनी निर्धारित की है, साथ ही यह भी बताना होगा कि परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचने के लिए केंद्रों पर क्या-क्या उपाय किए गये हैं। केंद्रों के नाम पते के साथ व्यवस्थापक की सूची भी मोबाइल नंबर के साथ शासन को देनी होगी।

29 जुलाई पर लगी मोहर

इससे पहले अनुमति मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड कोऑर्डिनेटर प्रो. अमिता वाजपेयी और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक राय के साथ हुई बैठक में 29 जुलाई को परीक्षा कार्ययें जाने की तिथि तय की गयी थी। इस संबंध में शासन को जानकारी भेजी गयी थी। इसके बाद सरकार ने भी अंतिम सहमति 29 जुलाई पर ही दी है।

20 जुलाई को जारी की जाएगी एडमिट कार्ड

29 जुलाई को होने वाली यूपी बीएड-2020 की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 जुलाई को जारी किया जायेगा। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड पर कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।

60 जिलों में आयोजित की जाएगी परीक्षा

बी एड प्रवेश परीक्षा परीक्षा के लिए इस बार साढ़े चार लाख से अधिक आवेदन आवे हैं। अभ्यर्थियों की भारी संख्या और कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अब यह परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित कराएगा। पहले यह परीक्षा प्रदेश के केवल 16 जिलों में आयोजित होनी थी।

बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कीं

7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

शासन ने 29 जुलाई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को हरी झंडी दे दी है। 28 अगस्त को परीक्षा परिणाम घोषित होंगे और 14 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। शासनादेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्रों में और यथासंभव जिला मुख्यालय के निकट ही बनाए जाएं। शासन ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित चहारदीवारी और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में वायस रिकार्डर व डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस कोना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक व कनिष्ठ द्वारा नामित एक अधिकारी होगा।



परीक्षा संचालन के लिए कमेटी : प्रत्येक जिले में परीक्षा संचालन व पर्यवेक्षण के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। कमेटी में डीएम द्वारा नामित अधिकारी के अलावा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक व कनिष्ठ द्वारा नामित एक अधिकारी होगा।

DAINIK JAGRAN Page 4

14 सितंबर से होगी बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग

संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रहे लविवि के प्रस्ताव



4.31 लाख विद्यार्थी होने शामिल

बीएड-2020 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब प्रदेश के 50 जिलों में ही होगी। कम आवेदन वाले जिलों को सूची हटाते हुए से परिलक्षित किया गया है। 29 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। लविवि के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह के मुताबिक एलयू के पाठ्यक्रमों को केन्द्रों की सूची जारी की जा सकती है। लविवि की ओर से बीएड की प्रवेश परीक्षा के केंद्रों की संख्या को लेकर मनन किया जा रहा है। कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यथासंभव पहले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। शासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए उससे बचाव निर्देश दिया है।

अभियार्थी हैं। शासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए उससे बचाव निर्देश दिया है।

निजी विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र

आर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 2020 के समय में शासनादेश जारी करते हुए लविवि से 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराया को कहा है। शासनादेश में नकल पर रखी से रोक दी बात कही गई है। इसके लिए निदेश दिया गया है। कमेटी में डीएम द्वारा नामित अधिकारी के अलावा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक व कनिष्ठ द्वारा नामित एक अधिकारी होगा।

50 जिलों में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा

उपर लविवि कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह के मुताबिक बीएड प्रवेश परीक्षा अब प्रदेश के 50 जिलों में होगी। पहले 73 जिलों में होती थी। 5 जुलाई को केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी। लविवि ने अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी जमाद के तीन केंद्र चुनने का विकल्प दिया गया था। 1 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने विकल्प चुने। सभी केंद्रों की समीक्षा करने के बाद जिलों की संख्या कम की गई है। ऐसे जमाद जहां तीन से ज्यादा केंद्र नहीं बन पा रहे थे, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई तक प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएंगे।

महाविद्यालयों से ई-मेल पर मांगा प्रस्ताव

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त महाविद्यालयों से केन्द्रीकृत प्रवेश के लिए ई-मेल पर प्रस्ताव मांगे हैं। लविवि ने ईमेल आईडी lkouniv.central.admission@gmail.com पर प्रस्ताव को जारी कर दिया है। महाविद्यालयों को पांच जुलाई तक प्रस्ताव, परास्नातक पाठ्यक्रमों की सूची, सीट संख्या समेत अन्य जानकारी पांच 5 जुलाई तक देनी होगी। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर इस तरह से लविवि भी केन्द्रीकृत दखिले करने जा रहा है। यहां लविवि का आवेदन फार्म करने वाले छात्रों को संयुक्त महाविद्यालयों में भी दखिले का मौका मिलेगा।

देना होगा शुल्क

इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए महाविद्यालयों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। महाविद्यालयों की व्यवसायिक पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 1 लाख रु. शुल्क 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ देना होगा। वहीं नामित पाठ्यक्रम के लिए प्रति पाठ्यक्रम 50 हजार रुपए व 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

AMRIT VICHAR Page 2

विश्वविद्यालय के साथ ही महाविद्यालय पूरी कर सकेंगे प्रवेश प्रक्रिया

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर सत्र 2020-21 से केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस केन्द्रीकृत प्रवेश प्रणाली के तहत इच्छुक संबद्ध महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही सम्पादित करा सकते हैं। इसके लिए कुलसचिव की ओर से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को 5 जुलाई, तक ईमेल में भेजे आवेदन पत्र के द्वारा केन्द्रीकृत प्रवेश प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए सूचना प्रेषित करने के लिए कहा गया है।

शासन ने 29 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की दी मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आगामी 29 जुलाई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने के लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर शासन ने सहमति दे दी है। बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न होने के बाद 28 अगस्त तक इसके परिणाम जारी होंगे। जबकि 14 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रवेश परीक्षा में इस बार 4.31 लाख छात्र शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग की तरफ से जारी आदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय से 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। शासन ने कहा है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी दशा में नकल न होने पाए। इसके लिए जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाए। यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्र यथासंभव केवल शासकीय महाविद्यालयों व विद्यालयों को ही बनाया जाए। पर्याप्त संख्या में राजकीय संस्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में अपरिहार्य स्थितियों में ही सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों व विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। किसी भी दशा में निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्रों में और यथासंभव जिला मुख्यालय के निकट ही बनाए जाएं। शासन ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित चहारदीवारी हो और सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हों। प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।

परीक्षा संचालन के लिए बनेगी कमेटी: शासन ने प्रत्येक जिले में परीक्षा के संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। कमेटी में डीएम द्वारा नामित अधिकारी के अलावा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक



एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी होंगे। परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षण के लिए एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी।

LU to begin centralised admissions: Now, fill one form for 170 colleges

System To Be Optional For Colleges

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: For the first time in its history, Lucknow University will conduct centralised admissions for associated colleges. The process will be like Delhi University's with the only difference being that LU's system is optional for the colleges. LU authorities on Thursday sent a proposal of the centralised system to all 170 associated colleges. Those accepting the proposal will have to pay Rs 50,000 (plus GST) each for admissions in regular undergraduate and postgraduate courses and Rs 1 lakh (plus GST) for self-financed courses. Colleges not opting for the system can hold their admission process separately. The major benefit of the centralised system would be that candidates will have to fill only one admission form instead of spending a huge amount on purchase of forms for various colleges. Further, LU will declare a merit list and conduct counselling for admissions. Candidates will get all the information regarding the admission process and results at one place rather than running around to different colleges. Another benefit would be that it is expected to put a check on anomalies in admissions. The move, if successful, will help cash-strapped LU generate extra revenue. Colleges have been asked to reply to the proposal by July 5 following which LU will decide on further action. However, a major hurdle in the process is that LU has taken the decision late. Many colleges have already started their admission process by releasing forms. Some might not opt for the centralised process because they will have to refund the application form fees to the candidates. LU vice-chancellor Prof



► For the first time in its history, LU plans to hold centralised admissions for its associated colleges
► There are 170 colleges associated with LU with 1.6 lakh UG and PG seats (regular and self-finance)
► The system will be like DU's with the difference that it will be optional for the colleges to join in
► Candidates will not have to apply at various colleges and will get all information at one place
► Colleges are to respond by July 5 on joining the process

AK Rai though said that even colleges which have released their forms can opt for the new system. The procedure would be simple. All candidates applying for admission to LU will also be given the option of admissions to colleges during the counselling process, depending on the availability of seats in a particular institution. It will be on first come, first served basis, he added. He said that centralised information about all the candidates will be maintained, thus reducing paper-work drastically.

4 new centres to teach science of happiness at LU

MohitaTewari@timesgroup.com

Lucknow: Four new institutes will be added to the ONGC multidisciplinary research centre of Lucknow University to help students excel in diverse areas. Besides giving wings to the ideas of budding engineers and churning out food toxicology experts, the institutes will teach students ways to stay happy. Being set up in LU's centenary year, the four centres of excellence — Happy Thinking Lab, Institute of Hydrocarbon, Institute of Food Processing, and Technology and Kalam Centre for Innovation — will be housed in end-computers with advanced software for quality research. LU executive council has given its nod to the centres and they will be run with the help of grants from the department of science and technology and corporate social responsibility. "Happy Thinking Lab is being set up to help students fight all negativities in life and learn the 'real meaning of happiness'. They will also be taught to apply happiness mantras in their future professional life," said LU vice-chancellor Prof Alok Kumar Rai. The lab will be open for students of MA psychology (50 seats) and those who opt for psychology under choice-based credit system. Kalam Centre of Innovation, under engineering faculty, will give wings to students' innovation through experimentation and development of technology and gadgets. It will also be open for students who wish to go for startups. The MSC food processing and food technology course with 30 seats, currently being run by the chemistry department, will be converted into a full fledged institute with its own lab and research paraphernalia. Earlier students had to go to other scientific institutes for research. "General public can also visit it for getting tests done to check the quality of food or adulteration at a nominal charge," said VC. Courses on mining and hydrocarbons, being run by the geology department, will be converted into an institute which will prepare students for career in the oil industry.